भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2974
दिनांक 10 मार्च, 2026 / 19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर

†2974. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के तटीय राज्यों की अवसंरचना पर चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) द्वारा किए गए अध्ययनों की संख्या का वर्ष-वार और आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) आन्ध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जोखिमग्रस्त अवसंरचनाओं की स्थिति और उन्हें स्थितिसह बनाने के लिए आवश्यक निवेश राशि के संबंध में ऐसे अध्ययनों के निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) सीडीआरआई द्वारा आन्ध्र प्रदेश में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है; और
(घ) अवसंरचनात्मक स्थिति को सुदृढ़ करने में ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क)**:** आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संघटन (सीडीआरआई) राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है। सीडीआरआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार**,** इसने प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में 15 भारतीय राज्यों में 23 पहलों का समर्थन किया है। सीडीआरआई द्वारा प्रदान किए गए विवरण अनुलग्नक में हैं।

(ख)**:** सीडीआरआई के वैश्विक अवसंरचना जोखिम मॉडल और रेसिलिएंस सूचकांक (जीआईआरआई) से प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के जोखिम अनुमानों से पता चलता है कि भारत में अवसंरचना का वार्षिक औसत नुकसान 31.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अध्ययनों से पता चलता है कि रेसिलिएंस डिजाइन में 10-15% के अतिरिक्त निवेश से परिहार्य नुकसानों के माध्यम से 7-12 गुना आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। राज्यवार जोखिम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग): सीडीआरआई ने विशाखापत्तनम बंदरगाह के लिए एक व्यवस्थित जलवायु जोखिम मूल्यांकन किया है। इसके दायरे में परस्पर जुड़े समुद्री बंदरगाह प्रणालियों में जलवायु जोखिमों का मूल्यांकन और रसद, ऊर्जा, परिवहन, श्रम और भंडारण नेटवर्क में क्रमिक व्यवधानों का आकलन शामिल है। प्रमुख सिफारिशों में भवन निर्माण संहिता को अद्यतन करना, प्रकृति-आधारित समाधानों का उपयोग करना, प्रारंभिक चेतावनी उपकरणों का एकीकरण, बहु-हितधारक समन्वय आदि शामिल हैं।

(घ): सीडीआरआई ने सूचित किया है कि इसने विद्युत, दूरसंचार, परिवहन और आपदा जोखिम वित्तपोषण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के उपायों के लिए सिफारिशें की हैं। विद्युत क्षेत्र की उपयोगिताओं पर सलाह जारी की गई है और विद्युत क्षेत्र पर अत्यधिक गर्मी के प्रभावों पर एक स्कोपिंग नोट भी जारी किया गया है। सीडीआरआई ने यह भी सूचित किया है कि इसने सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के दौरान आपदा जोखिम सूचकांक को अद्यतन करने के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान किए हैं।

***

<u>लोक सभा अता. प्र.सं. 2974, दिनांक 10.03.2026</u>

अनुलग्नक

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर के लिए देय लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2974 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

सीडीआरआई द्वारा समर्थित अध्ययन और पहलों की सूची

क्रम संख्या	क्षेत्र	परियोजना का शीर्षक	राज्य	वर्ष
1	दूरसंचार क्षेत्र	भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए आपदा जोखिम और रेजिलिएंस फ्रेमवर्क	असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड	2022-2025
2	परिवहन क्षेत्र (हवाई अड्डे)	हवाई अड्डों के आपदा रेजिलिएंस पर वैश्विक अध्ययन चरण-I	राष्ट्रीय (भारत सहित वैश्विक)	2022
3		हवाई अड्डों के आपदा रेजिलिएंस पर वैश्विक अध्ययन चरण-II	कर्नाटक, ओडिशा (भारत सहित वैश्विक)	2023-25
4		हवाई अड्डे की अनुकूलन क्षमता और अवसंरचना रेजिलिएंस को बढ़ाने हेतु जलवायु जोखिमों के बाबत तैयारी के उपायों का विकास	राष्ट्रीय (भारत सहित वैश्विक)	2025-26
5	परिवहन क्षेत्र (सड़क एवं रेल)	परिवहन अवसंरचना का पुनर्मूल्यांकन - रेजिलिएंस संबंध स्थापित करना	राष्ट्रीय (दक्षिण एशिया, भारत सहित)	2024-25
6		राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएँ विकसित करना	राष्ट्रीय	2024-25

लोक सभा अता. प्र.सं. 2974, दिनांक 10.03.2026

7	परिवहन क्षेत्र (बंदरगाह)	बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रणालीगत जोखिम मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित करना	आंध्र प्रदेश, ओडिशा	2023-25
8	स्वास्थ्य अवसंरचना रेजिलिएंस	सिक्किम में रेजिलिएंट स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए रोडमैप	सिक्किम	2023-25
9	रेजिलिएंट अवसंरचना के लिए वित्तपोषण	अवसंरचना परियोजनाओं में आपदा रेजिलिएंस को मुख्यधारा में लाना: भारत के अवसंरचना क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि	उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, असम	2023-25
10		महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों में आपदा के कारण राजकोषीय जोखिमों का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मूल्यांकन	राष्ट्रीय और ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश	2023-25
11		सोलहवें वित्त आयोग के लिए आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) अद्यतन	राष्ट्रीय	2024-25
12	शहरी रेजिलिएंस	चिकबल्लापुरा, बागेपल्ली, गौरीबिदानूर, शिदलाघट्टा, गुडीबांडे, चिंतामणि शहरों में छोटे शहरों में जल रेजिलिएंस का निर्माण	कर्नाटक	2025

लोक सभा अता. प्र.सं. 2974, दिनांक 10.03.2026

13	विद्युत अवसंरचना	विद्युत अवसंरचना पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव का अध्ययन – चरण-I	राष्ट्रीय	2024-25
14		ओडिशा में विद्युत क्षेत्र के रेजिलिएंस पर विद्युत अवसंरचना का अध्ययन	ओडिशा	2021-24
15	परिवहन क्षेत्र	पहाड़ी सड़कों के लिए राजमार्ग ढलान स्थिरीकरण प्रबंधन और रखरखाव के दिशानिर्देश	दक्षिण एशिया (भारत सहित)	2025
16		शिमला में रणनीतिक सड़कों का भूस्खलन जोखिम आकलन	हिमाचल प्रदेश	2023-24
17	बहुक्षेत्रीय	नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता पर इटली सरकार के साथ सहयोग	दक्षिण एशिया (भारत सहित)	2025
18		अत्यधिक गर्मी से राहत पाने के लिए शीतलन आश्रयों के डिजाइन, संचालन और रखरखाव के लिए दिशानिर्देश	राष्ट्रीय	2024-25
`19		एनडीएमए के माध्यम से तमिलनाडु के पीडीएनए के लिए सहायता	तमिलनाडु	2024-25
20		एनडीएमए के माध्यम से त्रिपुरा के पीडीएनए के लिए सहायता	त्रिपुरा	2024-25
21		एनडीएमए के माध्यम से मणिपुर के पीडीएनए के लिए सहायता	मणिपुर	2024-25
22		एनडीएमए के माध्यम से तेलंगाना के पीडीएनए के लिए सहायता	तेलंगाना	2024-25
23	शहरी	एनडीएमए के माध्यम से दिल्ली शहरी बाढ़ जोखिम शमन योजना और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार करने के लिए सहायता	दिल्ली	2025

******